भारत इज़्रराइल संबंधों का विवेचनात्मक अध्ययन

विशेषतः सन् 2000 से 2023

''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ''

राजनीति विज्ञान में

पी.एच.डी. की उपाधि हेतु

शोध प्रस्तावना

शोध निर्देशक	शोधार्थी
JV'n डॉ. सपना गहलोत	**JV'n** भागीरथ रेगर
राजनीति विज्ञान विभाग	**JVR-I/22/10071**

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर

2023

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृ.सं.
1	प्रस्तावना	
2	विषय एवं अध्ययन क्षेत्र	
3	अध्ययन की रूपरेखा	
4	शोध परिकल्पना	
5	शोध प्रश्न	
6	शोध उद्देश्य	
7	शोध प्रविधि	
8	साहित्य समीक्षा	
	संदर्भ ग्रंथ सूची	

प्रस्तावना

अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीपों को जोडने वाला और अन्धमहासागर, भूमध्यसागर एवं कालासागर से घिरा क्षेत्र पश्चिमी एशिया कहलाता है। पश्चिमी एशिया को एशिया और अफ्रीका का 'प्रवेश द्वार' तथा युरोप का **'पश्चिमी द्वार'** भी कहा जाता है। पश्चिमी एशिया में अरमानिया, अजरबेजान, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, जोजिया, ईरान, ईराक, इजरायल, जार्डन, टर्की, फिलीस्तीन, लेबनान, सउदी अरब, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, यमन आदि देश सम्मिलित किए जाते है।

इस क्षेत्र की भौगोलिक एवं जलवायविक परिस्थितियाँ– कठोर शुष्क जलवायु, मरूस्थलीय क्षेत्र की अधिकता, पर्याप्त जल संसाधनों का अभाव इत्यादि है। इस क्षेत्र के भूगर्भ में अवस्थित अकुत खनिज तेल सम्पदा के कारण यह क्षेत्र महाशक्तियों की रूचि का प्रमुख क्षेत्र रहा है इसके साथ–साथ युरोप व एशिया के मध्य व्यापार का प्रमुख मार्ग–स्वेज नहर जलमार्ग इसी क्षेत्र में अवस्थित है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख मार्ग है इसी कारण इस क्षेत्र पर महाशक्तियों द्वारा सदैव अपना प्रभाव स्थापित करने व अपने आधिपत्य को बरकरार रखने का प्रयास किया जाता रहा है। अपने वर्तमान स्वरूप में पश्चिमी एशियाई राजनीति का उद्भव प्रथम विश्व युद्ध से माना जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विदेश सचिव आर्थर बालफोर द्वारा फिलीस्तीन में यहुदी धर्मावलम्बियों के लिए ''राष्ट्रीय घर'' की स्थापना सम्बन्धी विचार व्यक्त किया।

यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व भी यहूदी धर्मावलम्बी संगठित रूप से इस दिशा में प्रयास कर रहे थे किन्तु **बालफोर घोषणा (2 नवम्बर 1917)** ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में पश्चिमी एशिया को केन्द्र बिन्दु में स्थापित किया।

बालफोर घोषणा के पश्चात् यहुदियों की राष्ट्रीय घर की स्थापना सम्बन्धी आशा प्रगाढ़ होती गई। इस घोषणा के पश्चात् यहूदी समुदाय द्वारा फिलीस्तीन की ओर पलायन करना **(आलियाह)** शुरू किया और फिलीस्तीन में बसने लगे। फिलीस्तीन भूमि पर निरन्तर बसते यहुदियों से मुस्लिम समुदाय का टकराव शुरू हुआ और अरब समुदाय द्वारा यहुदियों का प्रखर विरोध किया जाने लगा। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय के पश्चात फिलीस्तीन पर ब्रिटेन को शासनाधिकार प्राप्त हुआ यह शासनधिकार (मैण्डेट) प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में शान्ति संस्थापक संस्था राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन) द्वारा वर्ष 1922 में दिया गया था। इस शासनाधिकार का आधार **'स्काईज–पिकोट समझौता'** था जिसकी पुष्टि राष्ट्र संघ के 52 सदस्य राष्ट्रों द्वारा की गई। किन्तु अरब राष्ट्रों ने बालफोर घोषणा व स्काईज–पिकोट समझौते को उनके साथ धोखा माना।

इस समझौते के पश्चात् फिलीस्तीन में यहूदी जनसंख्या दोगुनी हो गई और अरब–यहूदी संघर्ष में कट्टरता और तीव्रता आयी जो इजरायल की स्थापना के बाद तक जारी रही।[1] वर्ष 1937 में ब्रिटेन द्वारा फिलीस्तीन में चल रहे अरब–यहूदी विवाद को हल करने हेतु लार्ड पील की अध्यक्षता में ''**फिलीस्तीन शाही आयोग**'' का गठन किया गया। इस आयोग को ''**पील आयोग**'' के नाम से भी जाना जाता है। पील आयोग ने अरब–यहूदी विवाद के समाधान हेतु फिलीस्तीन के विभाजन सम्बन्धी विचार व्यक्त किया। इस आयोग ने फिलीस्तीन को दो भागों–एक अरब और दूसरा यहूदी राज्य में विभक्त करने का सुझाव दिया। अरब समुदाय द्वारा पील आयोग के सुझावों को अस्वीकार्य बताया व ब्रिटेन पर इस आयोग की सलाह न मानने हेतु दबाव बनाया।[2]

इसी प्रकार अरब यहूदी विवाद के सन्दर्भ मे दोनों पक्षकारो को स्वीकार्य समाधान को तलाशने हेतु वर्ष 1939 में लंदन में **'सेन्ट जेम्स कॉन्फ्रेंस'** आयोजित की गई। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस की समाप्ति बिना उपयुक्त समाधान तलाशी के ही हो गई।

इस कॉन्फ्रेंस के अनुसरण में ब्रिटिश सरकार द्वारा ''श्वेत पत्र'' जारी किया गया। इस श्वेत पत्र के तहत यह घोषित किया गया कि फिलीस्तीन 10 वर्ष के संक्रमणकालीन समय के पश्चात् अरब बहुलता वाला स्वतंत्र राज्य बन जाएगा।

यद्यपि इस श्वेत पत्र को फिलीस्तीन के साथ–साथ सम्पूर्ण अरब जगत द्वारा अस्वीकार्य बताया गया।[3] द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिका और युरोपीय देशों द्वारा ब्रिटेन पर दबाव बनाया गया कि युरोप में नाजी शासन द्वारा किए गए यहूदी नरसंहार के पश्चात जीवित रहे यहुदियों को फिलीस्तीन आने की अनुमति प्रदान की जाए। इस प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् भी फिलीस्तीन समस्या के समाधान के सन्दर्भ में ब्रिटेन द्वारा किए जा रहे प्रयासों से भी इस समस्या का कोई उपयुक्त समाधान नहीं हो सका। इस असफलता ने ब्रिटेन को इसके समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ में अपील करने हेतु प्रेरित किया।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलीस्तीन विवाद के समाधान सम्बन्धी अपील को स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा फिलीस्तीन समस्या के अध्ययन हेतु एक आयोग ''**युनाइटेड नेशंस स्पेशल कमेटी ऑन फिलीस्तीन**'' (**UNSCOP**) का गठन 27 अप्रैल 1947 मे किया गया। इस आयोग ने 29 नवम्बर 1947 को महासभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में आयोग ने फिलीस्तीन विभाजन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे महासभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। भारत, पाकिस्तान व अरब देशों के प्रतिनिधियों सहित कुल 13 देशों ने फिलीस्तीन विभाजन के विपक्ष में मतदान किया। महासभा द्वारा प्रस्ताव को पारित किए जाने के पश्चात् अरब देशों द्वारा घोषणा की कि महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव को मानने के लिए वे बाध्य नहीं है। उन्हें यह अधिकार है कि वे उसी निर्णय को माने जो उनके विचार में उचित हो।[4]

29 नवम्बर 1947 को फिलीस्तीन विभाजन सम्बन्धी महासभा के प्रस्ताव 181 के पारित होने के पश्चात अरब समुदाय ने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनेक सवाल उठाए तथा इस मुद्दे के समाधान हेतु इसे अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपे जाने कि सिफारिश की। यद्यपि अरबों के विरोध का इस प्रस्ताव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और 14 मई 1948 को ब्रिटेन ने फिलीस्तीन पर मिले मैण्डेट की समाप्ति की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के एक आवश्यक कार्यकर्ता के रूप में स्वतन्त्र इजरायल राज्य की स्थापना सम्बन्धी घोषणा भी की गई। इस प्रकार यहुदियों के 'राष्ट्रीय घर' की स्थापना सम्बन्धी विचार 14 मई 1948 को वास्तविक बन सका ।

मई 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता सम्बन्धी इजरायल के आवेदन को स्वीकार कर लिया और इस पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा मई 1949 में प्रस्ताव 273 (iii) 35 पारित किया गया और इजरायल को संयुक्त राष्ट्र संघ के 59 वें सदस्य के रूप में सदस्यता प्रदान कि गई। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में इजरायल के प्रतिनिधि ने महासभा को आश्वस्त किया कि इजरायल संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धान्तों का पालन करेगा, घरेलु अधिकार क्षेत्र के प्रभावित होने के बावजुद भी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों का क्रियान्वयन करेगा।

भारत और इजरायल के मध्य निकटता :–

भारत और पश्चिमी एशिया के मध्य सम्बन्ध प्राचीन सभ्यताओं के काल से ही देखे जा सकते है। भारत व पश्चिमी एशिया मोहनजोदड़ो से लेकर वर्तमान ईराक की मेसोपोटामिया सभ्यताओं के समय से निकट रूप से जुडे हुए है। इसी प्रकार इस्लाम का जन्म पश्चिमी एशिया में हुआ और शनैःशनै इसका प्रसार शेष विश्व में हुआ। वर्तमान में इस्लाम धर्म हिन्दुओं के पश्चात् भारतीय समुदाय द्वारा माना जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा धर्म है।

ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारत–पश्चिमी एशिया सम्बन्धों में खलल अवश्य पड़ा किन्तु अवसर मिलते ही पुनः भारत और पश्चिमी एशिया में निकटता बढ़ने लगी। इसी प्रकार का एक सुअवसर भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान खिलाफत मुद्दे के दौरान आया। जब ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध में टर्की के खलीफा पद को समाप्त किया। टर्की के खलीफा पद को इस्लाम धर्मावलम्बी पवित्र पद मानते थे का भारत ने भी विरोध किया और भारत ने इस पद की पुनः बहाली हेतु महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत आन्दोलन किया।

अरब लोगों के साथ–साथ भारत के यहुदियों के साथ भी प्राचीन समय से ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहे है। भारत के राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी फिलीस्तीन विवाद के उद्भव से पूर्व ही यहूदी लोगों से निकट रूप से जुडे हुए थे। गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के दौरान हरमन कालेनबेच (Herman Kallenbach) और एच.एस.एल.पोलक जो कि यहूदी धर्मावलम्बी थे गांधीजी के निकट सहयोगी थे। इसी प्रकार गांधीजी की सहानुभूति भारत में निवासित यहुदियों के प्रति भी थी। गांधीजी को विश्वास था कि भारत में यहुदियों के प्रति अछुतों से भी निंदनीय व्यवहार किया जाता है। यद्यपि गांधीजी की सहानुभूति व सद्भाव यहुदियों के प्रति था फिर भी फिलीस्तीन मुद्दे पर गांधीजी के विचारों को इस सहानुभूति ने प्रभावित नहीं किया। गांधीजी ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद पर यहूदी लोगों की निर्भरता की आलोचना की। उन्होंनें कहा कि ''बाइबिल की अवधारणा का फिलीस्तीन एक भौगोलिक मार्ग नहीं है। यह उनके दिल में है लेकिन यदि यहूदियों द्वारा फिलीस्तीन को अपने राष्ट्रीय घर के रूप में देखा जाता है तो ब्रिटिश सैन्य बल के तहत इस क्षेत्र में यहुदियों का प्रवेश गलत है।''[9] गांधीजी को दृढ़ विश्वास था कि फिलीस्तीन मुद्दा नैतिक अर्थ लिए हुए है इसलिए इस विवाद का समाधान दोनों पक्षकारों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। उन्हें आशा थी कि बिना किसी अन्य देश की मध्यस्थता के यदि अरब देशों द्वारा यहुदियों को शरण दी जाती है तो यह उनकी पारम्परिक उदारता होगी।[10]

इसी प्रकार अहिंसा में पूर्ण आस्था रखने वाले गांधीजी ने कहा कि यदि मैं यहूदी होता तो उन्हें मैं बताता कि आतंकवाद का सहारा लेकर उन्होंने स्वंय अपने मामले को नुकसान पहुँचाया है। अन्यथा यह मामला उचित था। इसी सन्दर्भ में एक अमेरिकी पत्रकार से बातचीत करते हुए गांधीजी ने बल देकर कहा कि ष्इस मुद्दे का समाधान यहुदियों के आंतकवाद और हिंसा के पूर्ण परित्याग पर निर्भर करता है।''[11]

इजरायल की स्थापना, मान्यता के सन्दर्भ में भारतीय पक्ष :—

1917 में की गई बालफोर घोषणा के समय ही भारत ने फिलीस्तीन विभाजन का विरोध किया। इसी क्रम में इजरायल की स्थापना सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का भी भारत द्वारा अन्य अरब देशों के साथ विरोध किया गया। यद्यपि भारत और अरब देशों का फिलिस्तीन विभाजन सम्बन्धी विरोध सार्थक साबित नहीं हुआ और 14 मई 1948 को फिलीस्तीन पर ब्रिटिश मैण्डेट की समाप्ति के साथ ही एक स्वतन्त्र राज्य इजरायल की स्थापना हुयी।

इजरायल की स्थापना के कुछ समय पश्चात् ही संयुक्त राज्य अमेरिका व अन्य कुछ देशों द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई। 23 मई 1948 को इजरायल के राष्ट्रपति ने भारत से इजरायल को मान्यता दिए जाने का निवेदन किया लेकिन अरब देशों के दबाव तथा घरेलु राजनीति में पडने वाले प्रभावों के कारण भारतीय सरकार द्वारा इजरायल को मान्यता नहीं दी गई। इस सम्बन्ध में भारतीय प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने घोषणा की कि ष्भारत सरकार को इजरायल सरकार से मान्यता दिए जाने सम्बन्धी निवेदन प्राप्त हुआ है लेकिन वर्तमान में हम इस मामलें पर कोई कार्य नहीं करेंगें। भारत इस विवाद में कोई प्रभावी भूमिका न तो राजनयिक स्तर पर और न ही अन्य स्तरों पर निभा सकता है।''[17]

इजरायल को वर्ष 1949 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता मिलने के पश्चात् इजरायल के प्रति भारतीय दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और 17 सितम्बर 1950 को भारत द्वारा इजरायल को मान्यता (डी–ज्यूरे मान्यता) प्रदान की गई। भारत द्वारा इजायल को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में एक कानूनी इकाई के रूप में स्वीकार करते हुए मान्यता तो प्रदान कर दी गई लेकिन भारत ने इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बन्धो की स्थापना नहीं की गई। भारत ने इजरायल को मान्यता दिए जाने सम्बन्धी कृत्य के सन्दर्भ में अरब राष्ट्रों को आश्वस्त किया कि भारत का यह कार्य अरब देशों से मित्रता को प्रभावित नहीं करेगा।[18]

1948 से 1992 तक भारत–इजरायल सम्बन्ध :–

वर्ष 1948 में स्थापित इजरायल राज्य का अस्तित्व अरब राष्ट्रों के समान भारत को भी अस्वीकार्य था। अरब राष्ट्रों के समान भारत का भी मानना था कि इजरायल की स्थापना फिलीस्तीनी लोगों के साथ महाशक्तियों के द्वारा धोखा किया गया है। यद्यपि भारत व अरब राष्ट्रों के इजरायल से सम्बन्धित विरोध का कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसी क्रम में भारत ने भी अरब राष्ट्रों के समान इजरायल के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए मान्यता नहीं दी गई। यद्यपि भारत द्वारा इजरायल को मान्यता न दिए जाने के पीछे मूलतः दो कारण उतरदायी है। प्रथम–भारत की अरब देशों के साथ ऐतिहासिक मित्रता और दूसरा– भारतीय मुसलमानों की भावना का सम्मान करने हेतु । भारत की इस नीति में कुछ समय बाद परिवर्तन आया और भारत द्वारा 17 सितम्बर 1950 को इजरायल को मान्यता दी गई किन्तु इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना नहीं की। भारत द्वारा इजरायल को मान्यता दिए जाने के पश्चात् भारत–इजरायल सम्बन्धों का विवेचन अग्रवत है :–

वर्ष 1950 के पश्चात भारत व इजरायल के मध्य दूरियों को मिटाने हेतु शनैःशनैः प्रयास किए जाने लगे। इन्हीं प्रयासों के क्रम में 7 जून 1951 को

इजरायल द्वारा भारत में एफ.डब्ल्यु. पोलक को इजरायल के काउंसलर के रूप में नियुक्त किया गया जो कि इजरायल के भारत में ट्रेड कमिश्नर भी बनाए गए। 27 फरवरी से 9 मार्च 1952 तक इजरायल के विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल द्वारा भारत–इजरायल के मध्य औपचारिक राजनयिक सम्बन्धो की स्थापना हेतु द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। इस हेतु इजरायल के विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर जनेरल वाल्टेयर इयटान ने नई दिल्ली की यात्रा की लेकिन इस यात्रा का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। इसी क्रम में 3 अगस्त 1953 को भारत के बोम्बे शहर में इजरायल के काउन्सलेट का ऑफिस खोला गया।[19]

वर्ष 1956 के स्वेज संकट के दौरान भारत ने मिश्र का पक्ष लिया। इस समय भारत–इजरायल सम्बन्ध निम्नतम हो गए।[20] 1962 के भारत–चीन युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने विश्व के राष्ट्रों से सैन्य सहायता की अपील की। इस युद्ध में इजरायल द्वारा भारत को तुरन्त प्रभाव से सैन्य सहायता उपलब्ध करवायी। इसी प्रकार 1965 के भारत–पाकिस्तान युद्ध में भी इजरायल द्वारा आयुद्ध सामग्री व भारी मोटरार उपलब्ध करवाए।[21]

अरब–इजरायल विवाद के सन्दर्भ में भारतीय पक्ष को भारत के विदेश मामलों के मंत्री श्री एम.सी. छागला द्वारा संसद के दोनों सदनों में स्पष्ट किया।[22] श्रीमान छागला ने भारत की स्थिति के सन्दर्भ में पाँच महत्वपूर्ण पहलूओं को बताया गया जो निम्न है [23] :–

- इजरायल के अस्तित्व ने इजरायल और अरब देशों के बीच तनाव को पैदा किया है।
- मिश्र द्वारा सम्प्रभुता के अधिकार के तहत की गई माँग कि इस क्षेत्र से सयुंक्त राष्ट्र आपातकालीन सेना को निकल जाना चाहिए, प्रश्नगत नहीं किया चाहिए।

- भारत इस क्षेत्र से सयुंक्त राष्ट्र आपातकालीन सेना की वापसी का समर्थन करता है ।
- अकाबा की खाडी मिश्र का प्रादेशिक जल हैं।
- भारत–इजरायल की आक्रामकता से खतरा महसूस करता है।

जून 1967 के छह दिवसीय अरब–इजरायल युद्ध में पूर्व की भांति भारत ने अरब राष्ट्रों का समर्थन किया। इजरायल द्वारा इस युद्ध में वेस्ट बैंक, सिनाय प्रायद्वीप, गाजापट्टी, गोलन हाइट्स पर कब्जा किए जाने से इजरायल के प्रति भारतीय दृष्टिकोण और भी नकारात्मक हो गया। इस नकारात्मकता की पुष्टि इजरायल द्वारा सयुंक्त राष्ट्र आपातकालीन सेना में पदास्थापित भारतीय सैनिकों की हत्या ने और अधिक कर दी। भारत ने इस कृत्य की निंदा की और इसे जानबुझकर किया गया कृत्य करार दिया।[24] भारत ने इस कृत्य का औपचारिक विरोध भारत के मास्को स्थित दूतावास के माध्यम से दर्ज कराया और इस हेतु क्षतिपूर्ति की माँग की गई।

1973 में पुनः अरब–इजरायल विवाद के तहत युद्ध (योम किप्पुर युद्ध) हुआ। इस युद्ध के दौरान भी भारत ने पूर्व की भांति अरब देशों का समर्थन किया व उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। इसी क्रम में भारत के विदेश मंत्री श्री सरदार स्वर्ण सिंह ने 6 दिसम्बर 1973 को कहा कि अरब देशों के साथ हमारी सहानुभूति दो कारणों से है– प्रथम अरब जगत व भारत प्राचीन मित्र है। द्वितीय अरब प्राधिकार का इजरायली आक्रामकता द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

भारत की अरब समर्थक नीति के क्रम में ही भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 3379 का भी समर्थन किया इस प्रस्ताव के तहत जियोनिज्म को प्रजातिवाद के रूप में स्वीकार किया गया। यद्यपि वर्ष 1991 में इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। 10 अगस्त 1975 को नई दिल्ली में फिलीस्तीन छात्रों के जनरल यूनियन की बैठक को सम्बोधित करते हुए काग्रेंस अध्यक्ष **डी.के.बारू** ने

कहा कि षजियोनवाद के विरूद्ध फिलीस्तीन संघर्ष में हमारा पूर्ण सहयोग फिलीस्तीन के साथ है। उन्होंने यह भी कहा कि यह झुठे वादे पर आधारित है।[25]

इजरायल के प्रति भारतीय विदेश नीति में आंशिक बदलाव 1977–1980 में जनतादल के नेतृत्व वाली भारत सरकार में दिखाई देता है। जब भारत ने इजरायल के विदेश मामलों के मंत्री को भारत आने का निमंत्रण दिया यद्यपि जनवरी 1979 में सम्पन्न यह यात्रा दोनों पक्षकारों के मध्य राजनीतिक असहमति के कारण विफल रही।

वर्ष 1980 में पुनःसता में आए काग्रेंस दल ने पूर्व की भाँति इजरायल विरोधी नीति को अपनाकर फिलीस्तीन समर्थक नीति को बहाल किया। मार्च 1980 में भारत ने पी.एल.ओ. के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना की। ऐसा करने वाला भारत प्रथम गैर अरब देश बना तथा फिलीस्तीन के एक मिशन की स्थापना नई दिल्ली में की गई।[26]

श्रीमति इन्दिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात् भारतीय प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने विदेश नीति के सन्दर्भ में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया और न्यूयार्क में सयुंक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की।[27]

इसी क्रम में जुलाई 1987 में नई दिल्ली में आयोजित डेविस कप टेनिस टुनामेंट में इजरायली खिलाडियों को भागीदारी की अनुमति प्रदान की। सम्बन्धों की निकटता के क्रम में ही इजरायली विदेश मंत्रालय के एशिया विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जनरल जोसेफ हेदास ने दिसम्बर 1988 में भारत की यात्रा की और भारत के विदेश मंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव से मुलाकात की लेकिन भारतीय सरकार द्वारा इस यात्रा को एक पर्यटक यात्रा बताया गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में आयी भारत–इजरायल निकटता को सार्थक दिशा व नए पायदान पर प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिन्हा राव द्वारा पहुँचाया गया।

भारत–इजरायल सम्बन्ध वर्ष 1992 से वर्तमान तक :–

14 मई 1948 को अस्तित्व में आए इजरायल की स्थापना व भारत द्वारा 17 सितम्बर 1950 को इजरायल को मान्यता दिए जाने के पश्चात आगामी चार दशक तक भारत–इजरायल के मध्य सम्बन्ध निष्क्रिय रहे। वर्ष 1990 के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आए बदलाव–शीतयुद्ध का अंत, सोवियत संघ का विघटन, सर्वोच्च शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ता वर्चस्व, खाडी युद्ध के पश्चात अरब एकता में आया तनाव इत्यादि के साथ–साथ भारत की अनेक आन्तरिक चुनौतियों –भुगतान संतुलन की समस्या, पाकिस्तान व चीन द्वारा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतियों प्रस्तुत करना, भारत में दिन–प्रतिदिन बढ़ती आतंकवादी घटनाओं, साम्प्रदायिक दंगों, विभिन्न अलगाववादी संगठनों का मजबुत होता स्वरूप, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात नए रक्षा सहयोग साथी की तलाश इत्यादी ने भारत को इजरायल के प्रति अपनी विदेश नीति में बदलाव लाने व इजरायल के साथ मधुर सम्बन्ध बनाने हेतु प्रेरित किया।

इस प्रकार शीत युद्ध के पश्चात् परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में भारत में इजरायल समर्थक अल्पसंख्यक विचारों को महत्व मिला। इजरायल के साथ मधुर सम्बन्धों की स्थापना सम्बन्धी विचारों को महत्व निम्नलिखित तर्कों के आधार पर मिला :–

प्रथम :– इजरायल के साथ सम्बन्धों का दर्जा बढ़ाकर भारत स्वंय को पश्चिमी एशियाई शान्ति प्रकिया में शामिल करने की बेहतर स्थिति में होगा और इस प्रकार भारत फिलीस्तीन के प्रति इजरायली रूख को प्रभावित कर सकेगा।

द्वितीय :– भारत द्वारा इजरायल से पूर्ण राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना कर विकास हेतु आवश्यक उन्नत इजरायली तकनीकी प्राप्त कर सकेगा क्योंकि इजरायल व भारत लगभग समान भौगौलिक व जलवायविक, सामरिक परिस्थितियाँ रखते है। साथ ही युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप सैन्य

आधुनिकीकरण में इजरायली सैन्य तकनीकी कारगर साबित हो सकती है। इसके अलावा कृषि नवाचारों और भारत में वैश्विक यहूदी निवेश जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में भारत इजरायल से सहयोग प्राप्त कर सकेगा।

तृतीय :— अन्तिम तर्क के रूप में इस विचार को मान्यता मिली कि शीतयुद्ध के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ध्रुवीय व्यवस्था समाप्त नहीं हुयी अपितु शनैःशनैः इस्लामी गुट विश्व राजनीति में प्रभावी हो रहा है इसलिए फिलीस्तीन—इजरायल के प्रति भारत को अपने दृष्टिकोण, विदेश नीति में बदलाव कर इजरायल से मधुर सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए।

उपर्युक्त उल्लेखित तर्कों के अनुरूप इजरायल के प्रति भारतीय विदेश नीति में व्यापक बदलाव के संकेत प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव के शुरूआती कार्यकाल में ही देखने को मिला। इसका प्रमाण यह है कि भारत इजरायल के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए जियोनवाद को प्रजातिवाद के रूप में मानने वाले प्रस्ताव 3379 का वर्ष 1975 में भारत सह संस्थापक था ने वर्ष 1991 में महासभा में इस प्रस्ताव के निरसन के सम्बन्ध में मतदान दिया। भारतीय विदेश नीति में आए इस बदलाव की भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग, मीडिया समूह, विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा आलोचना की गई। किन्तु फिर भी भारतीय सरकार अपने निर्णय पर अडिग रही।[28]

वर्ष 1991 में भारतीय विदेश नीति में इजरायल के प्रति आए व्यापक बदलाव को वैधानिक स्वरूप प्रदान करते हुए भारत सरकार द्वारा 29 जनवरी 1992 को इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना की। भारत—इजरायल के मध्य सम्बन्धों के सामान्यीकरण के पश्चात् दोनों राष्ट्रों के मध्य द्विपक्षीय सम्बन्धों की प्रगाढता हेतु सार्थक प्रयास किए गए है। इन्हीं सार्थक प्रयासों के कारण विगत वर्षों में भारत—इजरायल सम्बन्धों के विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुयी है जो कि दोनों ही राष्ट्रों के लिए लाभकारी है। भारत—इजरायल

द्विपक्षीय सहयोगात्मक सम्बन्धों का अध्ययन चार श्रेणियों के तहत किया जा सकता है :–

राजनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं का अधिक आदान–प्रदान होता है जो कि भारत–इजरायल राजनीतिक सम्बन्धों में गर्मजोशी को प्रदर्शित करता है। भारत–इजरायल द्विपक्षीय सम्बन्धों का एक अन्य क्षेत्र आर्थिक सम्बन्ध है। भारत–इजरायल के मध्य वर्ष 1991 में जहाँ द्विपक्षीय व्यापार 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर था जो कि मुख्यता हीरे के व्यापार पर केन्द्रित था। भारत–इजरायल सम्बन्धों के सामान्यीकरण के पश्चात् भारत–इजरायल द्विपक्षीय व्यापार में न केवल विविधता आयी है अपितु इसमें शनैःशनैः वृद्धि हुयी। वर्तमान में भारत–इजरायल व्यापार वर्ष 2015–16 में 4955.53 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। वर्तमान में भारत–इजरायल के द्विपक्षीय व्यापार में आयात–निर्यात किए जाने वाले मुख्य उत्पादों में भारत से निर्यात सामग्री में बहुमूल्य पत्थर, रासायनिक उत्पाद, टैक्सटाइल इत्यादि वहीं इजरायल से भारत को सैन्य सामग्री, मशीनरी, खनिज उत्पाद, रासायनिक पदार्थ मुख्यतया पोटाश, समुद्री शैवाल, कपास इत्यादि शामिल है।

अर्थव्यवस्था और कृषि जैसे क्षेत्रों में भारत–इजरायल के बीच सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ–साथ भारत–इजरायल के मध्य प्रोद्यौगिकी हस्तांतरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी वृद्धि हुयी है। भारत द्वारा वर्ष 1991 में अर्थव्यवस्था में किए गए सुधारों–उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ने भी भारत–इजरायल सम्बन्धों को प्रगाढ़ करने में अति–महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

भारत–इजरायल के मध्य शीतयुद्धोत्तर काल में रक्षा एवं रणनीतिक सम्बन्धों में सर्वाधिक प्रगाढ़ता आयी है। यद्यपि भारत व इजरायल के मध्य आंशिक तौर पर रक्षा सम्बन्ध पूर्ण राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना के पूर्व भी रहे है। पूर्ण राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना के पश्चात् भारत इजरायल के मध्य रक्षा सम्बन्ध रक्षा उत्पादों व तकनीकी हस्तातरण, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद

का सामना इत्यादि क्षेत्रों में रहे है। वर्तमान में भारत–इजरायल के मध्य रक्षा सम्बन्ध केवल क्रेता–विक्रेता के ही नहीं बल्कि भारत व इजरायल द्वारा संयुक्त उद्यम के तहत रक्षा सामग्री का उत्पादन भी किया जा रहा है जैसे वर्ष 2017 में भारत व इजरायल द्वारा मध्यम दूरी की प्रहार क्षमता वाली बराक मिसाइल का विकास संयुक्त उद्यम के तहत ही किया गया है।

भारत–इजरायल सम्बन्धों की अन्य श्रेणी के तहत दोंनो देशों के मध्य विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण, चिकित्सा विज्ञान, अन्तरिक्ष अनुसंधान, उपग्रह प्रक्षेपण, अकादमिक सहयोग, सांस्कृतिक सम्बन्धों एवं पर्यटन को प्रोत्साहित करने इत्यादि क्षेत्रो में सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में भारत–इजरायल के मध्य अनेक सन्धि–समझौते सम्पन्न हुए है।

2. विषय एवं अध्ययन क्षेत्र

विषय : भारत इज्ञराइल संबंधों का विचनात्मक अध्ययन विशेषतः सन् 2000 से 2023

<u>अध्ययन क्षेत्र–</u>

भारत इज्ञराइल संबंधों का ऐतिहासिक सांस्कृतिक राजनैतिक–कूटनीतिक आयामों का विवेचनात्मक अध्ययन करना तथा दोनों देशों के मध्य सहयोग को बढ़ाने के प्रयासों का अध्ययन करना ।

भारत इज्ञराइल संबंधों में सहयोग के क्षेत्रो तथा तरीको आदि की पहचान करना तथा उनके लिए राजनीतिक, कुटनीतिक, सैन्य प्रयासो का अध्ययन करना ।

भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धान्तों का इज्ञराइल के संदर्भ में अध्ययन करना ।

3. अध्ययन की रूपरेखा

प्रस्तावित शोध के व्यवस्थित अध्ययन हेतु इसको भागों में बांटा जाएगा –

1. परिचय
2. भारत इज्राइल संबंधों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सम्बन्ध
3. भारत इज्राइल कूटनीतिक संबंध
4. भारत इज्राइल आर्थिक एवं सैन्य सम्बन्ध ।
5. निष्कर्ष

4. शोध परिकल्पना –

1. भारत–इज़राइल संबंध भारत के अमेरिका के साथ सम्बन्धों से प्रभावित रहे है।
2. भारत तथा इज़राइल सम्बन्ध अरब देशो के प्रभाव में रहे है।
3. भारत–इज़राइल सम्बन्धों पर भारत की घरेलु राजनीति का प्रभाव रहा ।
4. भारत–इज़राइल सैन्य सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका में रहा ।
5. आदर्शवादी भारतीय विदेश नीति के प्रभावस्वरूप भारत व इज़राइल के सम्बन्ध लम्बे समय तक प्रभावित रहे।

5. शोध प्रश्न

1. भारत–इज़राइल के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना ?
2. इज़राइल के संदर्भ में भारत के व्यापारिक हितों का अध्ययन करना?
3. भारत के इज़राइल के प्रति विदेश नीति में प्रमुख सिद्धान्तों का मूल्यांकन करना ?
4. भारत इज़राइल के साझा हितो पर कार्यो की पहचान करना ?
5. भारत इज़राइल सम्बन्धो में तकनीकी सहयोग की पहचान करना ?
6. हालिये घटनाक्रम और भारत–इज़राइल सम्बन्ध ?

6. शोध उद्देश्य

1. भारत–इज्रराइल संबंधों का ऐतिहासिक संबंधों का अध्ययन करना ।
2. भारत–इज्रराइल संबंधों में सहयोग के प्रमुख क्षैत्रों की पहचान करना।
3. भारत–इज्रराइल संबंध व भारतीय आदर्शवाद के संकट व अध्ययन करना।
4. भारतीय– इज्रराइल संबंध व वैश्विक आंतकवाद के खिलाफ सहयोग का अध्ययन ।

7. शोध प्रविधि –

प्रस्तावित शोध प्रविधि के अन्तर्गत ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जायेगा तथा इसके लिए आंकडो की प्राप्ति हेतु प्राथमिक डेटा तथा द्वितीयक आंकडों का उपयोग किया जाएगा तथा डेटा प्राप्ति हेतु पुस्तकों, रिसर्च पेपर, रिपोर्ट, लेख, पत्र–पत्रिकाएं, पाण्डुलिपि, पूर्व में हुए शोध अध्ययन आदि का उपयोग किया जाएगा ।

शोध साहित्य की समीक्षा :–

किसी भी प्रस्तावित शोध के लिए शोध शीर्षक से सम्बन्धित उपलब्ध साहित्य का अध्ययन उस शोध को सही दिशा देने हेतु अति आवश्यक है। भारत और इजरायल के पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रकाश डालने, उनका विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के सन्दर्भ में अनेक पुस्तकें, विदेश मंत्रालय के प्रतिवेदन व अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों के लेख प्रकाशित हुए हैं। भारत की विदेश नीति एवं इजरायल के अन्य देशों के साथ सम्बन्धों को केन्द्र मानकर अनेक अध्ययन एवं शोध सम्पादित हुए है। इन उपलब्ध शोध साहित्यों में भारत–इजरायल सम्बधों की विस्तृत चर्चा की गई है जिनमें से प्रमुख निम्न है :–

भारत–इजरायल सम्बन्धों पर **पी. आर. कुमार स्वामी** द्वारा लिखित ''**इण्डियाज इजरायल पॉलिसी**'' (India's Israel policy) नामक पुस्तक उल्लेखनीय है जिसका प्रकाशन 'कोलम्बिया युनिवर्सिटी प्रेस' द्वारा वर्ष 2010 में किया गया है। इस पुस्तक में लेखक पी.आर.कुमार स्वामी द्वारा भारत की इजरायल के प्रति विदेश नीति का विश्लेषण किया है। यह पुस्तक भारत के राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय से ही भारत के यहुदियों के प्रति रूख को स्पष्ट करती है। इस पुस्तक में भारत–इजरायल द्विपक्षीय सम्बन्धों का विस्तृत वर्णन किया गया है साथ ही भारत–इजरायल द्विपक्षीय सम्बन्धों को प्रभावित करने वाले कारकों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

भारत–इजरायल सम्बन्धों पर ''**डायनेमिक्स ऑफ डिप्लोमेसी डिलेयड इण्डिया एण्ड इजरायल**'' नामक पुस्तक भी उल्लेखनीय है जो **डॉ०आर. श्रीकांत नायर** द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का प्रकाशन 'कल्पाज पब्लिकेशन', नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2004 में किया गया है। लेखक डॉ०आर. श्रीकांत नायर द्वारा प्रस्तुत पुस्तक में पश्चिमी एशिया के प्रति भारत की विदेश नीति, फिलीस्तीन समस्या व इसके बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की बदलती विदेश नीति, का विस्तार से

विश्लेषण किया है। डॉ०नायर द्वारा प्रस्तुत पुस्तक में भारत–इजरायल सम्बन्धों के चुनौतिपूर्ण पक्ष, भारत–इजरायल द्विपक्षीय सम्बन्धों के साथ–साथ भारत–इजरायल की सामरिक बाध्यताओं का भी विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है।

भारत–इजरायल के मध्य आंतकवाद के विरूद्ध सहयोगात्मक सम्बन्धों की आवश्यकता को स्पष्ट करने के सन्दर्भ में **बी.एन.शर्मा** द्वारा लिखित पुस्तक **''इण्डिया एण्ड इजरायल अगेनेस्ट इस्लामिक टेरर : ओल्ड नेंशन, न्यू लीडर्स''** पुस्तक अति महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 2003 में मानस पब्लिकेशनश, नई दिल्ली द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में लेखक ने भूगोल, इतिहास व संस्कृति के आधार पर भारत–इजरायल की तुलना करने एवं इनकी सामान्य समानताओं का विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है।

नसीमा अख्तर द्वारा लिखी गई पुस्तक **''वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स''** जो कि दो खण्डों में लिखी गई है, का प्रकाशन श्ऑर्थर प्रेसश, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2004 में किया गया है। इस पुस्तक के प्रथम खण्ड **''इण्डियाज पॉलिसी टुवार्डस द फिलिस्तीन प्रोब्लम''** में लेखिका द्वारा फिलीस्तीन समस्या के ऐतिहासिक पहलु पश्चिमी एशिया व भारत की नीति, फिलीस्तीन विभाजन पर भारतीय पक्ष तथा फिलीस्तीन के विभाजन के पश्चात् भारतीय विदेश नीति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक के द्वितीय खण्ड **''रोल ऑफ इण्डिया एण्ड फिलीस्तीन''** में वर्ष 1970 के पश्चात भारत की पश्चिमी एशिया के प्रति अपनायी गई नीति व फिलीस्तीन से सम्बन्धों का वर्णन किया गया है।

प्रिया सिंह द्वारा लिखित पुस्तक **''फॉरेन पॉलिसी मेकिंग इन इजरायलः डॉमेस्टिक इन्फल्युनस : रिफ्लेक्शन ऑन द मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस''** का प्रकाशन शशिप्रा पब्लिकेशनश, दिल्ली द्वारा वर्ष 2005 में किया गया है। इस पुस्तक में लेखिका द्वारा इजरायल की घरेलु राजनीति और विदेश नीति के पारस्परिक अन्तःसम्बन्ध के बारे में बताया है तथा यह स्पष्ट किया है कि राज्य

का व्यवहार न केवल बाह्य घटनाओं से प्रभावित होता है बल्कि आन्तरिक दबाव भी विदेश नीति को प्रभावित करते है। प्रस्तुत अध्ययन इजरायल की विदेश नीति पर घरेलु राजनीति के प्रभाव को समझने का एक सैद्धान्तिक प्रयास है।

भारत–इजरायल सम्बन्धों के अध्ययन के सेन्दर्भ में ही 'न्यू सेंच्युरी पब्लिकेशन', नई दिल्ली, द्वारा प्रकाशित पुस्तक **''इण्डिया–वेस्ट एशिया रिलेशन्स अण्डरस्टेडिंग कल्चरल इन्टरप्लेज''** भी उल्लेखनीय शोध साहित्य है। इस पुस्तक का सम्पादन श्रीमान **इलियास और पी.जे. विनसेंट** द्वारा किया गया है। यह पुस्तक भारत और पश्चिमी एशिया सम्बन्धों के सांस्कृतिक पहलू का विश्लेषण करने के सन्दर्भ में एक प्रयास है। यह पुस्तक भारत और पश्चिमी एशिया सम्बन्धों के सन्दर्भ में विस्तृत शोध उपयोगी साहित्य उपलब्ध करवाती है।

हेम गॉरडॉन द्वारा लिखित पुस्तक **''इजरायल टूडे''** इजरायल से सम्बन्धित अध्ययन के सन्दर्भ में विश्वसनीय पुस्तक है। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में लेखक द्वारा जियोनिज्म, इसके इतिहास व वर्तमान में इसका अर्थ, इजरायली लोकतंत्र, इजरायली नैसेट तथा न्यायालय, इजरायल के अरब पडौसी, इजरायल के यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका से सम्बन्ध इत्यादि का विस्तृत उल्लेख किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन श्पीटरलंग पब्लिशिंगश न्यूयार्क द्वारा किया गया है।

घसिया ओबेद कायानी द्वारा लिखित पुस्तक **''पोस्ट 9/11 इण्डो–इजरायल रिलेशन्स''** का प्रकाशन 'एल ए पी लेम्बर्ट एकेडमिक पब्लिशिंग' द्वारा वर्ष 2012 में किया गया है। इस पुस्तक में लेखक कायानी ने अमेरिका पर हुए आंतकवादी हमलों के पश्चात बदले वैश्विक परिदृश्य मे भारत–इजरायल सम्बन्धों को प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में लेखक द्वारा यह बताया गया है कि दक्षिण एशिया और पश्चिमी एशिया के दो प्रमुख देश भारत और इजरायल सामरिक सम्बन्धों के बंधन में एक साथ बंधे हुए है। दोनों देश सुरक्षा से जुडे

सामान्य हित के कारण एवं 9/11 की आंतकी घटना से राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक सम्बन्धों को प्रगाढ़ करने हेतु बाध्य हुए है।

इसी क्रम में ''**फॉरेन पॉलिसी ऑफ इण्डिया एण्ड वेस्ट एशिया चेंज एण्ड कन्टयुनिटी**'' पुस्तक का सम्पादन '**फैजल मोहम्मद और राफ्लुलाह आजमी**' द्वारा किया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन 'न्यू सेंच्युरी पब्लिकेशन', नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2014 में किया गया है यह पुस्तक भारत के पश्चिमी एशिया के साथ बहुपक्षीय सम्बन्धों पर विस्तृत प्रकाश डालती है। इस पुस्तक में पश्चिमी एशिया का भारत की ओर आर्थिक झुकाव, ईरान के साथ भारत के आर्थिक सम्बन्ध, भारत की फिलीस्तीन नीति, ऐतिहासिक पहलू, महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू और फिलीस्तीन मुद्दा, भारत–इजरायल सम्बन्धों में फिलीस्तीन कारक, भारत–इजरायल सांस्कृतिक सम्बन्ध, भारतीय यहुदियों की भूमिका, आंतकवाद कि विरूद्ध लड़ाई में भारत–पश्चिमी एशिया सहयोग, अरब जगत पर वैश्वीकरण का प्रभाव इत्यादि विषयों पर विस्तृत प्रकाश डाला है।

भारत–इजरायल सम्बन्धों के अध्ययन से सम्बन्धित उपलब्ध साहित्य के क्रम में ही **निकोलस ब्लरेल** द्वारा लिखित पुस्तक ''**द इवोल्युशन ऑफ इण्डियाज इजरायल पॉलिसी कन्टयूनिटी, चेंज, एण्ड कॉम्परोमाइज सिन्स 1922**'' उल्लेखनीय है। इस पुस्तक का प्रकाशन 'ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस' द्वारा वर्ष 2015 में किया गया है। इस पुस्तक में लेखक द्वारा वर्ष 1922 से ही भारत की फिलीस्तीन के प्रति नीति तथा यहूदी लोगों के प्रति भारत के रूख को स्पष्ट किया है। इस पुस्तक में लेखक द्वारा 1948–1956, 1956–1974, 1984–1992 में भारत द्वारा इजरायल के प्रति अपनाए गए भारतीय दृष्टिकोण व भारत इजरायल सम्बन्धों को स्पष्ट किया है साथ ही लेखक द्वारा भारत–इजरायल के मध्य पूर्ण राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना के पश्चात् भारत–इजरायल द्विपक्षीय सम्बन्धों का भी विस्तृत उल्लेख किया है।

इसी क्रम में **श्रीमान अनवर आलम** द्वारा सम्पादित पुस्तक **''इण्डिया ग्लोबल पॉवरस एण्ड वेस्ट एशिया''** जिसका प्रकाशन 'न्यू सॅच्यूरी पब्लिकेशन' नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2011 में किया गया है उल्लेखनीय है यह पुस्तक भारत के आर्थिक हितों एवं महाशक्तियों की भूमिका का विस्तृत उल्लेख करती है। साथ ही भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में पश्चिमी एशिया की भूमिका को भी स्पष्ट करती है। इस पुस्तक में भारत के महाशक्तियों—संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, क्षेत्रीय शक्तियों व संगठनों के साथ बहुपक्षीय सम्बन्धों का विस्तृत वर्णन किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन के सन्दर्भ में **''इन्टरनेशनल रिलेशंसः कन्सैप्टस् एण्ड थ्योरीज''** नामक पुस्तक भी उल्लेखनीय है। जो **पी.वी. राठौड़** द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का प्रकाशन 'कॉमनवैल्थ पब्लिशर्स', नई दिल्ली से सन् 2004 में हुआ। लेखक पी.वी. राठौड़ द्वारा इस पुस्तक में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रकृति, आधार, सिद्धान्त व महत्व का व्यापक विवेचन प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में यह भी वर्णित किया है कि किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, कुटनीति, विदेश नीति, अन्तर्राष्ट्रीय कानून इत्यादि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसके व्यवहार को निर्धारित करते है। इस प्रकार इस पुस्तक में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के आधारभूत सिद्धान्तों का स्पष्टतया विवेचन किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति जो कि **चन्द्रशेखर सूद व निरंजन बहुगुणा** द्वारा रचित इस पुस्तक का प्रकाशन 'राधा पब्लिकेशन', नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2003 में किया गया है। इस पुस्तक के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का पूर्णतः सारतत्व प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में प्रथम विश्व युद्ध से वर्तमान तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हुए समझौतों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि परिस्थितियाँ समान होने पर भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में देशों के बीच आपसी सम्बन्धों का दौर दिन—प्रतिदिन बदलता ही रहता है।

फ्रेडरिक एल.शूमां द्वारा रचित ''**अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति**'' नामक पुस्तक जिसका प्रकाशन 'गया प्रसाद एण्ड सन्स पुस्तक पब्लिकेशन', आगरा से सन् 2004 में हुआ है फ्रेडरिक एल. शूमां ने इस पुस्तक के माध्यम से विश्व समस्याओं के अध्ययन हेतु आधार प्रस्तुत किया है। एक देश के दूसरे देश के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या सम्बन्ध हो इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

के.आर. गुप्ता द्वारा लिखी गई पुस्तक ''**इण्डियाज इटरनेशनल रिलेशंस**'' का प्रकाशन '**एटलैंटिक पब्लिशर्स**', नई दिल्ली, द्वारा वर्ष 2009 में किया गया है। यह पुस्तक भारत के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की स्थिति को पुर्णतया उजागर करती है। इस पुस्तक में भारत के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की स्थिति एवं उनकी परम्परागत नीति, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, स्वतन्त्र विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता इत्यादि बिन्दुओं को केन्द्र में रखकर भारत के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में आ रहे उतार–चढ़ाव को लेखक द्वारा इस पुस्तक मे वर्णित किया है। यह पुस्तक भारत के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में विश्व राजनीति में भारत की स्थिति को भी रेखाकिंत करती है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर प्रकाश डालती एक अन्य पुस्तक ''**भारतीय विदेश नीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध**'' है जो कि **अर्चना उपाध्याय** द्वारा लिखित है। इस पुस्तक का प्रकाशन श्संजय प्रकाशनश, नई दिल्ली द्वारा सन् 2005 में किया गया है। इस पुस्तक में भारतीय विदेश नीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्रियान्वयन का समावेश किया है। भारतीय विदेश नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य, विदेश नीति के सिद्धान्त, बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है। परमाणु निःशस्त्रीकरण समस्या, सी.टी.बी.टी., आंतकवाद की चुनौती जैसी वैश्विक समस्याओं के प्रति भारत के दृष्टिकोण को भी पुस्तक में अध्ययन का आधार बनाया गया है। भारतीय विदेश नीति के विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत करती हुई इस

पुस्तक में लेखिका अर्चना उपाध्याय द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में आए परिवर्तन एवं चुनौतियों का भी स्पष्टतया विवेचन किया गया है।

इसी क्रम में जे.एन. दीक्षित की पुस्तक **''भारत की विदेश नीति और आंतकवाद''** का प्रकाशन 'ज्ञान पब्लिशिंग हाउस', नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2006 में किया गया। यह पुस्तक भारत के विदेशी मामलों और उनमें हुयी प्रगति पर लिखे लेखों का एक संकलन है जो कि वर्ष 1994 से 2001 तक के समय पर आधारित है। इस पुस्तक में लेखक द्वारा भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण पक्षों जैसे—कश्मीर समस्या के सन्दर्भ में भारत—पाक सम्बन्ध, तालिबान समस्या, आंतकवाद, भारत के विदेश सम्बन्धों के उभरते आयाम इन सभी बिन्दुओं की विस्तारपूर्वक विवेचना की गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन हेतु **मथुरालाल शर्मा** द्वारा **''अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध''** पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक का प्रकाशन श्कॉलेज बुक डिपोश, जयपुर द्वारा वर्ष 2007 में किया गया। इस पुस्तक में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक घटनाक्रमों, राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों आदि के व्यावहारिक स्वरूप का विवेचन किया है। लेखक ने इस पुस्तक के माध्यम से प्रमुख देशों की विदेश नीतियों का यथासंभव वर्णन करते हुए उनके अन्य देशों के साथ सम्बन्धों को भी स्पष्ट किया है। द्वितीय महायुद्ध के बाद के शान्ति समझौतों, युद्धोत्तर विश्व, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख देशों की विदेश नीति व सम्बन्धों का स्पष्ट विवेचन लेखक द्वारा इस पुस्तक के माध्यम से किया गया है।

सन्दर्भ :–

1. प्रिंस रेंन्डॉल :– ''फास्ट फेक्ट ऑन द मिडल ईस्ट कॉन्फलिक्ट'' हारवेस्ट हॉउस पब्लिसर्श युगेन ओर्गऑन, यू.एस.ए. 2003, पृ.सं. 31
2. याकोव सिमोनी :– ''पॉलिटिकल डिक्शनरी ऑफ द अरब वर्ल्ड'' 'केटैर पब्लिशिंग हाउस', जेरूसलम, 1987, पृ.स. 14–15
3. निकोलस बेथल : ''द फिलीस्तीन ट्राइगल'' ए.डचः लंदन, यू.के., 1979, पृ. सं. 64
4. सुधा राव : ''द अरब इजरायल कॉन्फलिक्ट : द इण्डियन व्यू'', ओरियंटलॉगमैन लिमिटेड, नई दिल्ली, 1972, पृ.सं. 27
5. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बेलगाम अधिवेशन, दिसम्बर 1924, एनसाइक्लोपिडिया इण्डियन नेशनल कांग्रेंस (आई.एन.सी.), वॉल्यूम 8 पृ. सं. 681
6. एनसाइक्लोपिडिया ऑफ इण्डियन नेशनल कांग्रेस, वॉल्यूम 9 पृ.सं. 538
7. द असिंसियल राइटिंग ऑफ नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, दिल्ली, 1988 पृ. स. 197–219
8. जी. पार्थसारथी :– ''जवाहर लाल नेहरू लेटर्स टू चीफ मिनिस्टर्स 1947–1964'', वॉल्यूम 1. ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, पृ.स. 126
9. सुधा राव :– ''द अरब इजरायल कन्फलिक्टः द इण्डियन व्यू'', ओरियंटलॉगमैन लिमिटेड, नई दिल्ली, 1972, पृ.सं. 5
10. शिमोन एविमोर :– ''रिलेशंस बिटविन इजरायल एण्ड एशियन एण्ड अफ्रीकन स्टेटस : ए गाइड टू सलक्टेड डॉक्युमेंटेशन ''द हिब्रू युनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम, जेरूसलम, माओर वाल्लच प्रेस लिमिटेड, जेरूसलम, इजरायल 1991 पृ.सं. 18
11. फराह नाज ''इण्डो–इजरायल रिलेशंस : एन इवोल्युशनरी प्रस्पेक्टिव'' स्ट्रेटजिक एनालिसिस, वॉल्यूम 10, न. 13/2 आईडीसीए, नई दिल्ली, पृ. सं. 242

12. द स्टेटसमैन, 17–23 दिसम्बर, 1970

13. लोकसभा डिबेट 4, 25 मई 1966 पृ.सं. 871–876

14. एम.सी.छागला ''राजेज इन दिसम्बर, द ऑटोबॉयोग्राफी'' बोम्बे, 1973, पृ.सं. 23

15. लोकसभा डिबेट 4, 8 जून 1967, पृ.सं. 926

16. इन्टरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून 11 जनवरी 1975 पृ.सं.

17. मनोरमा 1993, पृ.सं.479

18. पी.आर. कुमारस्वामी :– ''इण्डिया–इजरायल रिलेशंसः हम्बल बिगनिगस, ब्राइट फ्यूचर'' द अमेरिकन ज्यूस कमेटी वाशिंगटन, यू.एस.ए 2002 पृ.सं.6.

19. निकोलस ब्लरेल :– ''द इवोल्यूशन ऑफ इण्डियाज इजरायल पॉलिसी, कन्ट्यूनिटी चेंज, एण्ड कॉम्परोमाइज सिन्स, 1922'', आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2015 पृ.सं. 243